

बहराइच।जिले में राजस्व विभाग की तरफ से सीजनल संग्रह अमीनों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर तमाम तरह के सरकारी बकाया, देयों के भुगतान की वसूली करसरकारी कोष में बढ़ोतरी का कार्य करने वाले लगभग 2 दर्जन सीजनल संग्रह अनुसेवक आज सरकार की अनदेखी के चलते भुखमरी की जिंदगी काटने को मजबूर हैं।

सीमावर्ती जिले बहराइच में सीजनल संग्रह अनुभाग की तरफ से लगाये जाने वाले ये सभी कर्मचारी अमीनों के साथ पिछले कई सालों तक बैंक लोन, बिजली बकाया भुगतान, खेत का लगान अदि तरह की आरसी जारी होने के बाद यही कर्मचारी सरकार के लिए सहयोगी के तौर पर अपनी सेवा देते चले आ रहे थे। शासनादेशों के मुताबिक 4 फसली की सर्वोत्तम सेवा करने वाले सभी सीजनल संग्रह कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तौर पर समायोजन करने का प्राविधान है। उसके बावजूद बहराइच जिले में सरकार के ये सहयोगी आज काफी अर्से से भुखमरी की जिंदगी काटने को मजबूर हैं, जबकि इनके साथी अमीनों को सरकार के आदेश पर समायोजित कर लिया गया है।

इस गंभीर प्रकरण पर जिले में कई बार दौरे पर आये उत्तर प्रदेश के, सरकार के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन, व चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल सहित प्रदेश के कई उच्चधिकारों के सामने भी इस प्रकरण को सामने रखने के बाद जल्द ही समायोजन का आश्वासन जरूर मिला लेकिन आज तक आश्वासन मात्र आश्वासन ही बनकर रह गया है। आलम ये है की नौकरी की आस में कई अनुसेवकों की तो जिंदगी की सांसे हमेशा के लिए थम गयीं, लेकिन आस अब तक पूरी नहीं हुयी। वहीं कुछ अपना परिवार चलाने के लिए रिक्शा चला कर गुजारा कर रहे हैं तो कुछ के लिए मजदूरी ही एक मात्र सहारा बचा है।

जिले के सीजनल संग्रह अनुसेवकों के मन को जब पत्रिका उत्तर प्रदेश की टीम द्वारा कुरेदा गया तो इतना दर्द झेलने के बावजूद सरकार भरोसा जताते हुए कहा की, समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव पर हमें आज भी पूरी भरोसा है की वो जल्द ही नौकरी में समायोजन का तोहफा जरूर देंगे। अब देखना है की पिछले कई वर्षों से बेरोजगार बनकर नौकरी में समायोजन की आस देखने वाले इन जरूरतमंद दर्जनों राजस्व विभाग के सीजनल संग्रह अनुसेवकों के समायोजन की बुनियादी मांग सरकार आखिर कब पूरी करती है।